रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-Section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 195] नई दिल्ली, मंगलवार, अप्रैल 4, 2000/चैत्र 15, 1922
No. 195] NEW DELHI, TUESDAY, APRIL 4, 2000/CHAITRA 15, 1922

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय

(विधायी विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 अप्रैल, 2000

सा. का. नि. 304 (अ).—राष्ट्रपति द्वारा किया गया निम्नलिखित आदेश सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है :—

"सं0 आ0 179"

संविधान (राजस्व वितरण) सं0 4 आदेश, 2000

राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 275 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए ग्यारहवें वित्त आयोग की, उसकी 2000-2001 के लिए अंतरिम रिपोर्ट में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर विचार करने के पश्चात्, निम्नलिखित आदेश करते हैं, अर्थात् :—

1. इस आदेश का संक्षिप्त नाम संविधान (राजस्व वितरण) सं0 4 आदेश, 2000 है ।

2. साधारण खंड अधिनियम, 1897 (1897 का 10), इस आदेश के निर्वचन के लिए उसी प्रकार लागू होगा जिस प्रकार वह किसी केन्द्रीय अधिनियम के निर्वचन के लिए लागू होता है ।

3. (1) अनुच्छेद 275 के खंड (1) के उपबंधों के अनुसार 1 अप्रैल, 2000 को प्रारंभ होने वाले वित्तीय वर्ष में, नीचे सारणी के स्तंभ (1) में विनिर्दिष्ट राज्यों में से प्रत्येक को राजस्वो की सहायता अनुदान के रूप में उक्त सारणी के स्तंभ (2) से (4) तक में उनके सामने विनिर्दिष्ट राशियां, संघ सरकार के, राज्यो की प्राकृतिक विपत्ति राहत निधियों के लिए अभिदाय, स्थानीय निकायों की सहायता के लिए सहायता अनुदान और रेल यात्री किराये पर कर के बदले में सहायता अनुदान, जो राजस्व प्रकृति के खर्च हैं, भारत की संचित निधि पर भारित होंगी :—

सारणी

	राज्य	राज्यों की प्राकृतिक विपत्ति राहत निधियों में संघ सरकार का अभिदाय	स्थानीय निकायों की सहायता के लिए राज्यों को सहायता अनुदान	रेल यात्री किराये पर कर के बदले में सहायता अनुदान
	(1)	(2)	(3)	(4)
			(रूपए लाखों में)	
1.	आन्ध्र प्रदेश	15556.39	15936.44	4756.50
2.	अरुणाचल प्रदेश	879.65	173.64	3.00
3.	असम	6265.89	5533.91	780.00
4.	बिहार	6508.55	21537.11	5316.00
5.	गोवा	134.33	221.64	110.43
6.	गुजरात	17484.69	9730.85	3933.57
7.	हरियाणा	3137.28	3721.03	1092.57
8.	हिमाचल प्रदेश	3375.61	1283.72	61.50
9.	जम्मू-कश्मीर	2469.96	1863.14	414.93
10.	कर्नाटक	5243.24	10949.32	1931.43
11.	केरल	6937.54	7659.57	1992.00
12.	मध्य प्रदेश	6395.89	15392.28	3922.50
13.	महाराष्ट्र	8540.85	17999.85	10002.57
14.	मणिपुर	311.99	432.78	10 50
15.	मेघालय	350.99	379.53	19.50
16.	मिजोरम	160.33	124.51	0.57
17.	नागालैंड	212.33	195.39	82.50
18.	उड़ीसा	6140.22	8254.37	977.43
19.	पंजाब	6781.55	5023.50	1869.57
20.	राजस्थान	22424.60	9578.22	2533.50
21.	सिक्किम	589.32	93.01	5.43
22.	तमिलनाडु	7435.87	15108.38	3681.00
23.	त्रिपुरा	563.32	561.42	22.50
24.	उत्तर प्रदेश	15673.39	33028.73	8874.00
25.	पश्चिमी बंगाल	6426.22	17017.65	4606.50
	योग :	150000.00	201800.00	57000.00

(2) राज्यों को स्थानीय निकायों की सहायता के लिए सहायता अनुदान के रूप में संदेय राशियों का अस्सी प्रतिशत राज्यों द्वारा ग्रामीण स्थानीय निकायों की सहायता के लिए और शेष राशि शहरी स्थानीय निकायों की सहायता के लिए उपयोग की जानी चाहिए ।

(3) उपपैरा (1) के अधीन संदेय कोई राशि या राशियां, अनुच्छेद 275 के खंड (1) के परन्तुकों मे से प्रत्येक के अधीन राज्यों को दी जाने वाली राशि या राशियों के अतिरिक्त होंगी ।

(4) उपपैरा (1) के अधीन संदेय कोई राशि या राशियां, वित्त आयोग की अंतिम रिपोर्ट के आधार पर किए जाने वाले और आदेश के अधीन रहते हुए, अनंतिम समझी जाएंगी ।

के.आर. नारायणन
राष्ट्रपति ।

[फा. सं. 19(4)/2000-वि-1]
सुभाष सी. जैन, सचिव

MINISTRY OF LAW, JUSTICE & COMPANY AFFAIRS
(Legislative Department)
NOTIFICATION
New Delhi, the 4th April, 2000

G. S. R. 304 (E).——**The following Order made by President is published for general information:-**

"C.O.179"

THE CONSTITUTION (DISTRIBUTION OF REVENUES) No. 4 ORDER, 2000

In exercise of the powers conferred by article 275 of the Constitution, the President, after having considered the recommendations of the Eleventh Finance Commission contained in their Interim Report for 2000-2001, hereby makes the following Order, namely:—

1. This Order may be called the Constitution (Distribution of Revenues) No. 4 Order, 2000.

2. The General Clauses Act, 1897 (10 of 1897) shall apply for the interpretation of this Order as it applies for the interpretation of a Central Act.

3. (*1*) In accordance with the provisions of clause (1) of article 275, there shall be charged on the Consolidated Fund of India, in the financial year commencing on the 1st day of April, 2000, as grants-in-aid of the revenues of each of the States specified in column (1) of the Table below, the sums specified against it in columns (2) to (4) of the said Table, towards expenditure, of revenue nature, on Union Government's contribution to States' Calamity Relief Funds, grants-in-aid to assist local bodies and grants-in-aid in lieu of tax on railway passenger fares mentioned in those columns:—

TABLE

State	Union Government's contribution to States' Calamity Relief Funds	Grants-in-aid to States to assist local bodies	Grants-in-aid in lieu of tax on railway passenger fares
(1)	(2)	(3)	(4)
		(Rupees in lakhs)	
1. Andhra Pradesh	15556.39	15936.44	4756.50
2. Arunachal Pradesh	879.65	173.64	3.00
3. Assam	6265.89	5533.91	780.00

(1)	(2)	(3)	(4)
4. Bihar	6508.55	21537.11	5316.00
5. Goa	134.33	221.64	110.43
6. Gujarat	17484.69	9730.85	3933.57
7. Haryana	3137.28	3721.03	1092.57
8. Himachal Pradesh	3375.61	1283.72	61.50
9. Jammu and Kashmir	2469.96	1863.14	414.93
10. Karnataka	5243.24	10949.32	1931.43
11. Kerala	6937.54	7659.57	1992.00
12. Madhya Pradesh	6395.89	15392.28	3922.50
13. Maharashtra	8540.85	17999.85	10002.57
14. Manipur	311.99	432.78	10.50
15. Meghalaya	350.99	379.53	19.50
16. Mizoram	160.33	124.51	0.57
17. Nagaland	212.33	195.39	82.50
18. Orissa	6140.22	8254.37	977.43
19. Punjab	6781.55	5023.50	1869.57
20. Rajasthan	22424.60	9578.22	2533.50
21. Sikkim	589.32	93.01	5.43
22. Tamil Nadu	7435.87	15108.38	3681.00
23. Tripura	563.32	561.42	22.50
24. Uttar Pradesh	15673.39	33028.73	8874.00
25. West Bengal	6426.22	17017.65	4606.50
Total:	150000.00	201800.00	57000.00

(*2*) Eighty per cent. of the sums payable as grants-in-aid to States to assist local bodies should be used by the States to assist the rural local bodies and the remaining amount to assist the urban local bodies.

(*3*) Any sum or sums payable under sub-paragraph (*1*) shall be in addition to any sum or sums payable to the States under each of the provisos to clause (1) of article 275.

(*4*) Any sum or sums payable under sub-paragraph (*1*) shall be treated as provisional subject to further Order to be made on the basis of the final report of the Finance Commission.

K.R. NARAYANAN,

President.

[F.No. 19(4)/2000-L I]

SUBHASH C. JAIN, Secy.

Printed by the Manager, Govt of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054 – 2000